

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 10 एमजेडडब्ल्यु जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 135 के पत्थर नं0 171/370 (20) किला नं0 23/2/164, 24/2/164, 25/2/153 व पत्थर नं0 171/371 (25) किला नं0 3 से 5 कुल 1.240 हैक्टर भूमि अनकमाण्ड मुशतरका खाता में दर्ज है जिसमें मुझ वादी का 0.373 हैक्टर भूमि का हिस्सा है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंगन वाद-पत्र है।

यह कि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेख में मुशतरका खाता में दर्ज है, लेकिन वादी व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदा व किस्म कीमत के लिहाज से व रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अर्सा दराज पूर्व अपने हक हिस्सा की भूमि का घराघरु बंटवारा किया हुआ है व घराघरु बंटवारानुसार वादी को चक 10 एम जेड डब्ल्यु के प0नं0 171/370 (20) किला नं0 23/2/056 (किला नं0 24 से चिपती हुई) किला नं0 24/2/164, 25/2/153 कुल .373 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है व वादी घराघरु बंटवारा में प्राप्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है लेकिन उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में मुशतरका दर्ज होने से उक्त आराजी के सीव वट आदि बाबत विवाद रहता है जिससे वादी अपने हक व हिस्सा की घरु बंटवारा में प्राप्त चक 10 एम जेड डब्ल्यु के प0नं0 171/370 (20) किला नं0 23/2/056 (किला नं0 24 से चिपती हुई) किला नं0 24/2/164, 25/2/153 कुल .373 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम से अलग-अलग खाता व रकम कायम करवाना चाहता है जिसका कि वादी अधिकारी व दावेदार है।

अध्यक्ष कलक्टर  
उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे मुताबिक घराघरू बंटवारा राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से दर्ज करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे व आखिर गत् सप्ताह मुकाम 10 एमजेडडब्ल्यू में स्पष्ट इन्कार हो गये यही बिनाये वाद है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 इस भूमि का भू-धारक है। जिससे उन्हे पक्षकार बनाया गया है। कि वाद-पत्र वादी बाबत तकसीम खाता का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/- रुपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे:-

क) कि वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्षितानुसार वादी को विभाजन में प्राप्त चक 10 एमजेडडब्ल्यू के प0नं0 171/370 (20) किला नं0 23/2.056 (किला नं0 24 से चिपती हुई) किला नं0 24/2.164, 25/2.153 कुल 0.373 हैक्टर कृषि भूमि का वादी के नाम अलग से खाता व रकम कायम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वादी पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी पक्ष अपने कब्जा काश्त के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। इसलिए वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय के मत में कोई भी पक्ष अपना कब्जा साबित करने में सफल नहीं हुआ है, अतः वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर वादग्रस्त खाता के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार हनुमानगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि:- चक 10 एमजेडडब्ल्यू खाता सं. 135 में दर्ज तादादी 1.240 हैक्टर आराजी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों की उपस्थिति में विधि सम्मत पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर समस्त सह-काश्तकारों के हिस्सानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में अच्छी-मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर, आगामी तारीख पेशी 07.08.2025 तक भिजवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को अलग से तहरीर जारी हो। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) एस  
सहायक कलेक्टर  
एवं अपर सहायक कलेक्टर  
हनुमानगढ